अधिवक्ता मौलिक अधिकारों के रक्षक की भूमिका निभाते हैं- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने द बार एसोसिएश्न जयपुर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ दिलाई

जयपुर, 23 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता कानून की कठिन भाषा को सरल बनाकर समाज को न्याय दिलाने वाले सेतु हैं।

सोमवार को बनीपार्क स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में दी बार एसोसिएशन जयपुर के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अधिवक्ता संविधान एवं मौलिक अधिकारों के रक्षक तथा लोकतंत्र के प्रहरी की भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं को न केवल पेशेवर मंच प्रदान करता है, बल्कि बौद्धिक विमर्श, नैतिक अनुशासन और सामूहिक शक्ति का भी केंद्र है।

उन्होंने कहा कि यह संस्था विधिक सुधारों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। 42 नए न्यायालय स्थापित किए गए हैं। फलौदी, खैरथल-तिजारा सहित कुल 8 जिला एवं सेशन न्यायालयों का सृजन किया गया है। लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशेष अदालतों एवं फास्ट ट्रैक तंत्र को अधिक सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की न्यायसंगत मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को बनीपार्क स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में दी बार एसोसिएशन जयपुर के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित किया।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं को न केवल पेशेवर मंच प्रदान करता है, बल्कि बौद्धिक विमर्श, नैतिक अनुशासन और सामूहिक शक्ति का भी केन्द्र है।**

कार्यक्रम में हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल उपमन ने कहा कि राज्य के बजट से विधि क्षेत्र को थोड़ी निराशा हुई है। उन्होंने अदालत परिसर और संसाधनों की जरूरत बताते हुए कहा कि सरकार को विधि क्षेत्र के लिए भी ध्यान देने की जरूरत है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि अधिवक्ता वर्ग की समस्याएं हैं, उनका निराकरण किया जाएगा।

कार्यक्रम में सीएम ने एसोसिएशन के निर्वाचित अध्यक्ष सोमश चन्द शर्मा व महासचिव उमेश चौधरी एवं जिला बार एसोसिएशन के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई।

ट्रंप कहा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी इस तथाकथित सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति को और घेरने की रणनीति बना रही है। वे लोगों को टैरिफ पेमैंट तुरंत आगे बढ़ाने के लिए कानून बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने डॉनल्ड ट्रंप को एक चिड़चिड़े, आवेगी, बिना सोचे-समझे काम करने वाले और हठी व्यक्ति के रूप में उजागर किया है।

उनके कदमों का जो भी परिणाम हो, वे अपनी प्रतिशोध की योजनाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस फैसले के बाद, शी जिनपिंग के साथ डॉनल्ड ट्रंप की आगामी बैठक साफ तौर पर एकतरफा होगी।

बारां में 40 करोड़ रूपए के अवैध विस्फोटक व पटाखे पकड़े गए

बारां, 23 फरवरी (निसं)। अटरू-बारां मेन रोड स्थित मंडोला के पास फर्म आर.डी. ब्रदर्स के तीन गोदामों में अवैध विस्फोटक निर्माण सामग्री और भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण मिलने पर पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त टीम ने छापेमारी कर करीब 40 करोड़ रुपये की सामग्री जब्त कर तीनों गोदामों को सील कर दिया।

अभिषेक अंदासु, पुलिस अधीक्षक बारां ने बताया कि 20 फरवरी को सूचना मिली थी कि गोदामों में अत्यधिक मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री जमा की गई है, जिससे आसपास के रहवासियों की जान को खतरा हो सकता है। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कोतवाली पुलिस, नगर परिषद और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। निरीक्षण के दौरान भारी मात्रा में सूतली बम, पटाखे और विस्फोटक निर्माण सामग्री पाई गई।

- **पुलिस ने आर.डी. ब्रदर्स के तीन गोदाम सील किए।**

पुलिस और प्रशासन ने आर.डी. ब्रदर्स के तीन गोदामों से भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक निर्माण सामग्री और पटाखे जब्त किए हैं। जब्त सामग्री की बाजार कीमत करीब 40 करोड़ रुपए आंकी गई है।

अभिषेक अंदासु, पुलिस अधीक्षक बारां ने बताया कि सूचना मिलने पर संयुक्त टीम ने छापा मारकर तीनों गोदाम सील कर दिए। कार्रवाई में 1350 कट्टे सूतली बम (338 क्विंटल), 5500 कार्टन पटाखे (1918 क्विंटल), 12 क्विंटल विस्फोटक कच्चा माल, 130 बोरी जर्दा (45 क्विंटल), पैकिंग मशीन, लाल बत्ती व अन्य सामग्री जब्त की। फर्म के खिलाफ थाना कोतवाली बारां में मामला दर्ज किया गया है। गोदामों में अग्निशमन सुरक्षा उपकरण नहीं मिले।

बांग्लादेश में भारी सैन्य फेरबदल किया नई सरकार ने

बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान एक्शन मोड में आए

नई दिल्ली, 23 फरवरी। तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम पद की शपथ लेने के साथ ही रहमान ने देश में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। रहमान ने सेना में टॉप लेवल पर बड़ा फेरबदल किया है।

तारिक रहमान ने ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हफीजुर रहमान को भारत से बांग्लादेश वापस बुला लिया है। हफीजुर रहमान भारत में बांग्लादेश हाई कमीशन में डिफेंस एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे थे।

- **रहमान ने भारत में कार्यरत बांग्लादेश हाईकमीशन के डिफेंस एडवाइज़र हफीज़ुर रहमान को भी वापस बुला लिया है।**

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, इन बदलावों का असर कई अहम स्ट्रेटेजिक कमांड्स के साथ-साथ बांग्लादेश की सबसे बड़ी मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी पर भी पड़ेगा।

पीएम रहमान ने भारत में बांग्लादेश हाई कमीशन में डिफेंस एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हफीजुर रहमान को मेजर जनरल के रैंक पर प्रमोट किया है और 55वीं इन्फैंट्री डिवीजन का जीओसी नियुक्त किया है।

आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से जारी किए गए ये बदलाव प्रधानमंत्री तारिक रहमान की नई सरकार के 17 फरवरी को सत्ता संभालने के कुछ दिन बाद हुये हैं।

तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने 12 फरवरी को हुए चुनावों में दो-तिहाई बहुमत हासिल किया। तारिक रहमान ने 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही मुहम्मद यूनुस का 18 महीने का शासन खत्म हुआ।

महाराष्ट्र में विपक्षी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

(एमवीए) के पार्टनर्स शिवसेना (उद्धव ठाकरे), कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार) के बीच टकराव की अटकलों को जन्म दे दिया है।

महाराष्ट्र से सात राज्य सभा सीटें रिक्त होने जा रही हैं। इन सीटों में से दो कांग्रेस के पास हैं, एक शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के पास और एक एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के पास है। राज्य सभा के चुनाव में मतदान विधायक करते हैं और 2024 महाराष्ट्र चुनावों में एनडीए की शानदार जीत के कारण इन सात सीटों में से छह सीटें एनडीए की झोली में जा सकती हैं। इसका मतलब है कि विपक्ष के पास केवल एक सीट बचती है। शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के नेता उद्धव ठाकरे कथित तौर पर दिल्ली यात्रा की योजना बना रहे हैं, ताकि कांग्रेस के उच्च नेतृत्व से बातचीत की जा सके। इस बीच, सूत्रों ने बताया कि एनसीपी (शरद पवार) प्रारंभिक बातचीत का हिस्सा नहीं रही है, जिससे विपक्षी खेमे के भीतर समीकरणों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

राज्य सभा की 37 सीटों के लिए चुनाव 16 मार्च को आयोजित होने हैं। इस साल सेवानिवृत्त होने वाले महाराष्ट्र के सांसदों में एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार, शिवसेना (यूबीटी) की प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस की डॉ. फौजिया तहसीन अहमद खान और राजानी अशोक राव पाटिल शामिल हैं। अन्य तीन भाजपा के डॉ. भागवत किशनराव कराड, धैर्यशील और सहयोगी रामदास अठावले हैं।

रांची से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसी बीच चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत करमाटांड़ गांव के पास स्थित जंगल में स्थानीय लोगों ने विमान का मलबा देखे जाने की सूचना दी। बाद में चतरा जिला पुलिस-प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची स्थानीय लोगों के सहयोग से राहत कार्य चलाया।

'भारत टैक्सी दुनिया की सबसे पारदर्शी कैब सर्विस बनेगी'

केन्द्रीय गृहमंत्री अमितशाह ने भारत टैक्सी के सारथियों (चालक) के साथ संवाद में कहा

नई दिल्ली, 23 फरवरी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि हाल ही में शुरू की गई सहकारी टैक्सी सेवा "भारत टैक्सी" अपने मंच से जुड़े सभी 'सारथियों' (चालकों) के लिए प्रति किलोमीटर न्यूनतम आधार किराया सुनिश्चित करेगी और इस दर से नीचे सेवा संचालित नहीं की जाएगी।

शाह ने कहा, भारत टैक्सी में ऑटो की लागत, पेट्रोल की खपत और न्यूनतम लाभ को जोड़कर बेस रेट निर्धारित किया जाएगा। यह सेवा पारदर्शिता के सिद्धांत पर काम करेगी और किसी भी बदलाव की सूचना एक सप्ताह पहले सारथियों को मोबाइल पर दी जाएगी। अमित शाह ने कहा, भारत टैक्सी में कुछ भी छिपा नहीं होगा। सारथियों को नोटिफिकेशन के ज़रिए हर जानकारी देने से 'भारत टैक्सी' दुनिया की सबसे पारदर्शी कैब सर्विस बनेगी। भारत टैक्सी सारथियों की मिनिमम वायबिलिटी के आधार पर एक

- **शाह ने कहा, यह सहकारी टैक्सी सेवा सभी सारथियों के लिए प्रति किलोमीटर न्यूनतम किराया तय करेगी।**

बेसलाइन किलोमीटर रेट तय करके चलेगी। भारत टैक्सी में ऑटो के मूल्य, पेट्रोल की खपत और मिनिमम प्रॉफ़िट को मिलाकर एक बेस रेट बनाया जाएगा और सर्विस इस रेट से नीचे नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य किसी निजी कंपनी की तरह अधिकतम मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि सारथियों को सशक्त बनाना है। इस सहकारी मॉडल में सारथी ही मालिक होंगे और 500 रुपये का शेयर लेकर साझेदार बन सकेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव में सारथियों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी, ताकि वे स्वयं अपने हितों की रक्षा कर सकें।

किश्तवाड़ में सेना ने सात खुंखार आतंकी मारे

जम्मू, 23 फरवरी। किश्तवाड़ जिले के चतरू क्षेत्र में 326 दिनों तक चले एक संयुक्त अभियान में सात खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सेना की वाइट नाइट कोर ने इस अभियान को वीरतापूर्ण दृढ़ ता बताया और कहा कि किश्तवाड़ के चुनौतीपूर्ण भूभाग और खराब मौसम की स्थिति में अथक और कठिन अभियान चलाए गए।

सेना ने कहा कि वाइट नाइट कोर के जवानों ने जम्मू और कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के समन्वय से नागरिक और सैन्य खुफिया एजेंसियों के सुव्यवस्थित खुफिया नेटवर्क के आधार पर कार्रवाई की। सुरक्षा बलों ने भीषण ठंड और जमा देने वाली ठंड में दुर्गम पहाड़ी इलाकों में आतंकवादियों का पीछा किया, जिसके परिणामस्वरूप कई बार मुठभेड़ हुई और अंततः सभी सात आतंकवादियों को मार गिराया गया।

नीट -पीजी कट-ऑफ कम होने का क्या असर होगा?

नई दिल्ली, 23 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह इस बात की पड़ताल करेगा कि नीट-पीजी के कट ऑफ मार्क्स को घटाने से क्या चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है या नहीं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने नीट-पीजी के कट ऑफ मार्क्स को घटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।

सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि ये फैसला खाली सीटों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। उन्होंने कहा कि नीट पीजी न्यूनतम चिकित्सकीय योग्यता प्रमाणित कने के लिए नहीं है, बल्कि सीमित सीटों के बीच उम्मीदवारों की तुलना कर सेलेक्शन के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें सभी अभ्यर्थी पहले से एमबीबीएस डिग्रीधारी डॉक्टर हैं।

- **सर्वोच्च न्यायालय चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर इसके प्रभाव की जांच करेगा।**

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील गोपाल शंकरनारायणन ने फीस असमानता का भी मसला उठाया। उन्होंने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फीस 9 हजार से 27 हजार रुपये तक होती थी जबकि निजी कॉलेजों में 95 लाख से 1.50 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है। उन्होंने कहा क 50वें पर्सेंटाइल तक लगभग 1.3 लाख छात्र सीट उपलब्ध होने के बावजूद काफी ज्यादा फीस के कारण निजी कॉलेजों में प्रवेश नहीं ले पाते। उन्होंने निजी कॉलेजों की फीस की सीमा तय करने की मांग की।

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 26 फरवरी को

नई दिल्ली, 23 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 26 फरवरी तक टाल दी है। जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज की सुनवाई सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता के उपलब्ध नहीं होने की वजह से टाली।

- **हालांकि सोमवार 23 फरवरी को सुनवाई होनी थी पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के नहीं आने से सुनवाई टाल दी गई**
- **यह याचिका सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने दायर की है जिनमें कहा है कि जिन चार वीडियो के आधार पर सोनम को गिरप्तार किया गया है, वे उन्हें दिखाए तक नहीं गए हैं।**

गीतांजलि ने 19 फरवरी को उच्चतम न्यायालय से कहा था कि जिन चार वीडियो के आधार पर गिरफ्तार किया गया वो वीडियो सोनम वांगचुक को दिखाया ही नहीं गया। केवल पेन ड्राईव में थंबनेल दिखाया गया और उसे प्ले नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान सोनम वांगचुक के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि वीडियो उपलब्ध नहीं कराना अधिकारों का उल्लंघन है। बिना वीडियो देखे सलाहकार बोर्ड और सरकार के समक्ष कोई अपनी बात कैसे रख सकता है। उन्होंने कहा था कि डीआईजी एक लैपटॉप के साथ आए और चार वीडियो बताया गया। सोनम वांगचुक को 5 अक्टूबर, 2025 को लैपटॉप उपलब्ध कराया गया जिसमें चारो वीडियो नहीं थे, केवल थंबनेल दिखाया गया। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज ने कहा कि एक वीडियो है जिसमें सोनम वांगचुक और डीआईजी के बीच बातचीत हो रही है। उस वीडियो में सब खुलासा हो जाएगा।

उच्चतम न्यायालय ने 16 फरवरी को जोधपुर जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि वो सोनम वांगचुक को हिरासत के दौरान दी गई पेन ड्राईव सीलबंद कर कोर्ट में दाखिल करें। उच्चतम न्यायालय ने इस बात का संदेह जताया था कि केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक के भाषणों से संबंधित जो ट्रांसक्रिप्ट दी है उसके अनुवाद में काफी फर्क है।

सुनवाई के दौरान 8 जनवरी को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चौरी-चौरा कांड का जिक्र करते हुए कहा था कि हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल तत्काल वापस ले लिया था। आपको याद होगा कि गांधीजी ने भी ऐसा ही किया था। जब चौरी-चौरा की घटना के बाद हिंसा हुई थी, तो उन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही किया था। सिब्बल ने कहा कि हिरासत में लेने के 28 दिन बाद उनको हिरासत में लेने के आधार बताए गए जो कानूनी समय-सीमा का साफ उल्लंघन है।

भारत की पहली आतंकरोधी नीति "प्रहार" जारी की केन्द्र सरकार ने

नई दिल्ली, 23 फरवरी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को भारत की पहली व्यापक आतंकवाद-रोधी नीति जारी की। इसे "प्रहार" नाम दिया गया है। इस नीति में सीमा पार से होने वाले आतंकवाद, साइबर हमलों, ड्रोन और उभरती तकनीकों के गलत इस्तेमाल जैसे खतरों का प्रमुखता से जिक्र किया गया है। नीति में यह भी बताया गया है कि केवल सीमा पार से होने वाला आतंकवाद ही खतरा नहीं है, बल्कि आपराधिक हैकर और अन्य राष्ट्र भी भारत को निशाना बना रहे हैं।

मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए रणनीति दस्तावेज में कहा गया है कि भारत आतंकवाद को किसी खास धर्म, जाति, राष्ट्रीयता या सभ्यता से जोड़कर नहीं देखता। इसमें यह भी कहा गया है कि देश लंबे समय से सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहा है, जिसमें जिहादी आतंकवादी संगठन और उनके मुखौटा संगठन लगातार हमलों की योजना बना रहे हैं।

- **गृह मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड इस नीति में कहा गया है भारत आतंकवाद को धर्म या जाति से जोड़कर नहीं देखता।**

नीति में अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठनों के नाम का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि ये जासूसों (स्लीपर सेल) के जरिये भारत में हिंसा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। नीति में यह भी बताया गया है कि सीमा पार से साजिशकर्ता उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर पंजाब और जम्मू-कश्मीर में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ ा है। आतंकवादी समूह अब संगठित आपराधिक नेटवर्क का इस्तेमाल अपने संचालन और नई भर्ती के लिए कर रहे हैं।

लोकसभा अध्यक्ष अपने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है, स्पीकर की गलतियों व कृत्यों के कारण उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया गया है।

लोकसभा स्पीकर ने वैश्विक लोकतांत्रिक संबंधों को मजबूत करने के नाम पर 60 से अधिक देशों के साथ संसदीय मित्रता समूहों का गठन किया है और इसके लिए बड़ी रकम खर्च की जा रही है। लोकसभा स्पीकर के पास एक विवेकाधीन कोष होता है, लेकिन इसका ऑडिट नहीं होता, क्योंकि वह एक संप्रभु अधिकारी हैं, और इस कोष के खर्च पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता और न ही इस पर चर्चा हो सकती है। यही स्थिति भारत के राष्ट्रपति के कोष के साथ भी है।

विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता इन समूहों का नेतृत्व करेंगे, जो भारत की लोकतांत्रिक विविधता और शक्ति को 60 से अधिक देशों के सामने उजागर करेंगे।

जो नेता इन प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करेंगे, उनमें पी. चिदंबरम, शशि थरूर, रवि शंकर प्रसाद, टी.आर. बालू, के.सी. वेणुगोपाल, अखिलेश यादव, ओवैसी, अभिषेक बनर्जी, सुप्रिया सुले और अनुराग ठाकुर शामिल हैं।

इसके अलावा, रामगोपाल यादव, गौरव गोगोई, कनिमोई करुणानिधि, मनीष तिवारी, डैरेक ओ ब्रायन, राजीव प्रताप रूडी, संजय सिंह, बैजयंत पांडा, निशिकांत दुबे, भर्तहरी महताब, डी. पुरंदेश्वरी, संजय कुमार झा, हेमा मालिनी और प्रफुल्ल पटेल भी महत्वपूर्ण देशों के साथ मित्रता समूहों का नेतृत्व करेंगे।

यहां बनाए गए मित्रता समूहों में शामिल कुछ महत्वपूर्ण देश हैं:

श्रीलंका, जर्मनी, न्यूज़ीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, इज़राइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात।

पहले चरण में, 60 से अधिक देशों के साथ मित्रता समूह स्थापित किए गए हैं, और अतिरिक्त देशों के साथ इसका विस्तार करने की भी योजना है।

जल्दी ही अलवर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को शामिल करता है, तथा इससे राज्य सरकारों के शहरी और नगर निगम विभागों के साथ समन्वित दृष्टिकोण विकसित हो रहा है।

राष्ट्रीय राजधानी रेल परिवहन निगम ने उत्तर प्रदेश सरकार से विचार-विमर्श करके, वित्तीय उपकरणों, जैसे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) और वैल्यू कैप्चर फाइनेंस (वीसीएफ) के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार की है।

नई दिल्ली के सराय काले खान को आरआरटीएस मल्टी-मॉडल हब और प्रारंभिक स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है, जिसे भविष्य की आरआरटीएस लाइनों के साथ एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनमें प्रस्तावित दिल्ली-अलवर और दिल्ली-करनाल रैपिड रेल कॉरिडोर शामिल हैं। केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा कि केन्द्रीय मन्त्रिमंडल जल्द ही इन दो नए आरआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी देगा।

असम में कांग्रेस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इनमें से 25 सीटें कांग्रेस ने और 16 सीटें बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ ने जीती थीं। लेकिन इस बार कांग्रेस एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन करने के पक्ष में नहीं दिख रही है, क्योंकि राज्य में उसकी स्थिति कमज़ोर मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव में धुबरी सीट पर खुद बदरुद्दीन अजमल को कांग्रेस के रकीबुल हुसैन ने 10 लाख वोटों से हराया था। कांग्रेस ने एआईयूडीएफ को भाजपा की "बी टीम" भी कहा है। छोटी पार्टियों के अलावा, कांग्रेस इस साल के चुनाव के लिए शिवसागर के विधायक अखिल गोगोई की पार्टी रायजोर दल के साथ गठबंधन की संभावना पर विचार कर रही है। कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि 2021 में सीटों का अंतर बड़ा था, लेकिन वोट प्रतिशत में अंतर बहुत कम था। एनडीए को 43.9 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि महाजोत को 42.3 प्रतिशत वोट मिले थे, यानी वोट प्रतिशत में केवल 1.6 प्रतिशत का अंतर था।

हालांकि भाजपा के प्रचार अभियान का नेतृत्व कर रहे असम के मुख्यमंत्री हिमन्ता बिस्वा सरमा की आक्रामक शैली कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होगी, लेकिन गांधी उनके सामने प्रभावी जवाब बन सकती हैं। यह भी संभावना है कि सरमा प्रियंका पर सीधे हमले से बचें।

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि राज्य में भाजपा के मजबूत संगठन को देखते हुए, अगर पार्टी चुनाव सीधे तौर पर नहीं भी जीतती है, लेकिन अपनी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार करती है, तो भी गांधी के प्रयासों को सफल माना जाएगा।

अनिल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बीडीओ एलएलपी का सिग्नेटरी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, इसलिए कार्रवाई रोक दी जाए। तीनों बैंकों ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। बैंकों का कहना था कि फोरेंसिक ऑडिट वैध है, रिपोर्ट में फंड के गलत इस्तेमाल की बात है। बैंकों ने दलील दी कि सिंगल जज का आदेश ग़लत और परवर्स है।

डिवीजन बेंच ने अपील स्वीकार करते हुए कहा कि निचली अदालत का आदेश कानूनी रूप से सही नहीं था। कोर्ट ने कहा कि अब बैंकों को आगे की कार्रवाई से रोका नहीं जा सकता।

हरदीप पुरी के बारे में नया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विवाद को और बढ़ाने वाली खबरें यह भी हैं कि रॉबर्ट मिलॉर्ड नामक व्यक्ति, जिसे कुछ रिपोर्टों में एपस्टीन का करीबी बताया गया है, ने कथित तौर पर हिमानी पुरी, जो हरदीप पुरी की बेटी हैं – से जुड़े एक कारोबारी उपक्रम में लगभग 2,400 करोड़ रुपये का निवेश किया।

मीडिया के कुछ हिस्सों और ऑनलाइन मंचों पर फैल रहे इन दावों ने इस राजनीतिक विवाद को आर्थिक पहलू भी दे दिया है। हालांकि, जांच एजेंसियों की ओर से इस कथित निवेश की प्रकृति, आकार या वैधता के संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

हरदीप सिंह पुरी, जिन्होंने पहले भी सार्वजनिक मंचों पर अन्य आरोपों का जवाब दिया है, ने इन ताजा दावों पर अभी तक कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया है। पहले के मामलों में वे यह कहते रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह की गलत गतिविधि से जोड़ने की कोशिश राजनीतिक रूप से प्रेरित है और तथ्यों पर आधारित नहीं है।

इस बीच विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने सावधानी भरा रुख अपनाया है। पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने तुरंत कोई आरोप लगाने से परहेज किया। पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी की शोध टीम सामने आए नए दस्तावेजों की जांच कर रही है और सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद ही पार्टी अपना रुख स्पष्ट करेगी। उन्होंने कहा, "हम किसी निष्कर्ष पर जल्दबाजी में नहीं पहुंचना चाहते। सभी तथ्य स्पष्ट होने के बाद ही पार्टी अपनी स्थिति बताएगी।"

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि दस्तावेजी साक्ष्य की पुष्टि होती है या केन्द्रीय एजेंसियां इन दावों पर संज्ञान लेती हैं, तो यह मुद्दा और गंभीर हो सकता है। संसद सत्र अक्सर आरोप-प्रत्यारोप से गरम रहते हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में यह विवाद संसद तक भी पहुंच सकता है।

फिलहाल यह मामला सार्वजनिक मंचों पर दावों और प्रतिदावों तक सीमित है। ये खुलासे औपचारिक जांच का रूप लेते हैं या केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहते हैं, यह काफी हद तक ठोस साक्ष्य और आधिकारिक स्पष्टीकरण पर निर्भर करेगा।

असम के सीमावर्ती ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

देती है। अमित शाह की यात्रा का मुख्य आकर्षण "वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम" (वीवीपी) के दूसरे चरण का औपचारिक लॉन्चिंग है, जो कछार जिले के सीमावर्ती गाँव नाथनपुर से की गई। इस कार्यक्रम के लिए 6,839 करोड़ रुपये का भारी बजट निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य दूरदराज़ के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है, ताकि प्रवासन पर काबू पाया जा सके और यहाँ के निवासियों को सुरक्षा के लिए देश के प्राथमिक "आंख और कान" के रूप में सशक्त बनाया जा सके।

यह सीमा चौकियों की धारणा को "अंतिम गांव" से बदलकर "भारत के पहले गांव" में परिवर्तित करता है।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित काचर, भाजपा को घुसपैठ और सीमा सुरक्षा पर अपने मुख्य फोकस को फिर से तेज करने का अवसर प्रदान करता है। ये मुद्दे असम में इसकी राजनीतिक पहचान के केन्द्र बिंदु रहे हैं।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600